



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102023-249130
CG-DL-E-04102023-249130

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 250]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2023

मामला संख्या: एडी (एसएसआर) - 08/2023

विषय: चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण., वियतनाम और ताइवान में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" के आयात के संबंध में निर्णायक पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 07/20/2023-डीजीटीआर.—मैसर्स टेक्रोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित), के अनुसार चीन जन.गण., जापान, कोरिया गण., वियतनाम और ताइवान (बाद में 'संबद्ध देशों के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (बाद में 'विषय वस्तुओं' के रूप में संदर्भित किया जाता है) के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू करने की मांग की गई है।

2. अधिनियम की धारा 9ए(5) और एडी नियमों के नियम 23(1बी) के अनुसार, लगाए गए पाटन रोधी शुल्क जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता, ऐसी तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। प्राधिकरण को

पाटन रोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। उसी के अनुसार, प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन रोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता है, और क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. पृष्ठभूमि

3. संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.05.2019 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.05.2020 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए थे जिसमें निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।
4. . उक्त सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 29.07.2020 की सीमा शुल्क संख्या 21/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क 28.07.2025 तक लागू हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स ("विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "विषय वस्तुएं" या "डिजिटल प्लेट्स" या "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स") हैं।
6. मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला गया उत्पाद क्षेत्र निम्नानुसार था:

"विचाराधीन उत्पाद "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग मुद्रण उद्योग में कागज पर या गैर-अवशोषक सबस्ट्रेट जैसे टिन शीट या पॉली फिल्म आदि पर एक छवि के रूप में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग करके मुद्रण प्रक्रिया में डिजिटल वर्कफ्लो सीधे स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। लेज़रों का उपयोग करके 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) में छवि, एनालाग वर्कफ्लो के विपरीत जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्लेटें रासायनिक कोटिंग से लेपित उच्च शुद्धता वाले लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बनाई जाती हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें या तो सकारात्मक (गैर-उजागर क्षेत्र छवि बनाती हैं) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र छवि बनाती हैं) कार्यशील प्लेटें हो सकती हैं। इस श्रेणी में वे प्लेटें शामिल हैं जिन्हें प्लेटों के प्रसंस्करण के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है; और पर्यावरण के अनुकूल भी, जिसके प्रसंस्करण के लिए किसी रसायन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए कोटिंग फॉर्मूलेशन अलग-अलग होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट तीन प्रकार की होती हैं,

I. थर्मल प्लेट्स

II. वायलेट प्लेट्स

III. सीटीसीपी / यूवी सीटीपी प्लेट्स

प्राधिकरण ने प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और माना है कि सभी आयामों और मोटाई में सभी प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आती हैं। हालांकि, ऊपर बताए गए कारणों से वाटरलेस सीटीपी प्लेटों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

7. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहता है।
8. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 29 में दर्शाया गया है।

ग. समान वस्तु

9. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और विषय देशों से आयातित विषय वस्तुएं वस्तुओं की तरह हैं। विषय देशों से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और विषय देशों से आयातित डिजिटल प्लेटे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधीन हैं और इसलिए नियमों के तहत 'जैसे लेख' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देशों से आयात किए जा रहे विषय वस्तुओं के लिए 'जैसे लेख' के रूप में माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन मैसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कथित पाटित की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित नहीं है। हालांकि आवेदक ने अपनी दो विनिर्माण इकाइयों के नियमित रूप से बंद होने के कारण विषय और गैर-विषय दोनों देशों से विषय वस्तुओं की नगण्य मात्रा का आयात किया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि पीओआई के दौरान उनके द्वारा किए गए आयात विषय वस्तुओं के उत्पादन की तुलना में कम मात्रा में थे। आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य प्रमुख उत्पादक है अर्थात् एचएल प्रिंटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। भारत में कुल घरेलू उत्पादन में से आवेदक का उत्पादन हिस्सा 96% है। चूंकि आवेदक का उत्पादन भारत में विषय वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए आवेदक स्थिति को संतुष्ट करता है और पाटन रोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है।

ड. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण., जापान, कोरिया गण., वियतनाम और ताइवान है।

च. जांच की अवधि

12. वर्तमान समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक है। क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई तक है।

छ. प्रक्रिया

13. निर्णायक समीक्षा जांच में दिनांक 15.05.2020 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित अंतिम निष्कर्षों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा जिसमें संबंधित देशों में उत्पन्न होने वाली या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है।
14. नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

ज. पाटन की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

15. प्राधिकरण की सतत प्रथा चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मानने की रही है जब तक कि चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते हैं कि पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है।
16. इसलिए वर्तमान जांच शुरू करने के उद्देश्य से उचित लाभ मार्जिन के साथ-साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित आवेदक के उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है।

जापान, कोरिया, वियतनाम और ताइवान के लिए सामान्य मूल्य

17. आवेदक ने आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर विषयगत देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि विषयगत देशों में लागत को प्रतिबिंबित करने के लिए सामग्री, उपयोगिताओं और श्रम के लिए विधिवत समायोजित है।
18. प्राधिकारी ने, जांच शुरू करने के उद्देश्य से, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित मुनाफे के लिए विधिवत समायोजित उत्पादन आवेदक के लागत के आधार पर प्रथम दृष्टया जापान, कोरिया, वियतनाम और ताइवान के लिए सामान्य मूल्यों का निर्धारण किया है।

निर्यात कीमत

19. प्राधिकरण ने शुद्ध निर्यात मूल्य (एनईपी) के निर्धारण के लिए विषय वस्तु के सीआईएफ मूल्य पर विचार किया है। इसके बाद प्राधिकरण ने एक्स-फैक्ट्री कीमत पर पहुंचने के लिए इन कीमतों में आवश्यक समायोजन किया है।

पाटन मार्जिन

20. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध और डंपिंग या क्षति की पुनरावृत्ति

21. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क मौजूद होने के बावजूद संबद्ध देशों से आयात की मात्रा अधिक बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने मौजूदा पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति की पुनरावृत्ति की प्रथम दृष्टया संभावना की जांच की है। प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया आवेदन में कथित आधारों के आधार पर मौजूदा शुल्कों की निरंतरता की भी जांच की है।
22. इसके अलावा, आवेदक ने सकारात्मक डंपिंग और क्षति मार्जिन, डंपिंग का इतिहास, संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताएं और क्षमता विस्तार, संबद्ध देशों में घरेलू मांग की कमी, शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग पर डंपिंग की पुनरावृत्ति का संभावित प्रभाव जैसे कारकों के आधार पर क्षति की संभावना का दावा किया है। पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की संभावना के बारे में प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

ञ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और खुद को संतुष्ट करने के बाद, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर घरेलू उद्योग को डंपिंग और परिणामी क्षति की संभावना की पुष्टि करते हुए, और नियम 23 के अनुसार नियमों के (1बी) में, प्राधिकरण विषयगत देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए वर्तमान जांच शुरू करता है, और यह जांचने के लिए कि क्या मौजूदा वस्तुओं की समाप्ति हो रही है पाटन रोधी शुल्क से पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान होगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
25. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक

जानकारी दर्ज कर सके। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

26. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।
27. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
28. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जांच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ठ. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
30. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
31. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है, उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
33. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
34. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
35. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।
36. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995

- के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
37. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 29 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।
38. सार्थक अगोपनीय अंश के बिना किया गया कोई अनुरोध या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार गोपनीय दावे संबंधी किसी अनुरोध को पर्याप्त और पूरे कारणों के विवरण के बिना प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
39. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
40. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकारी ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।
41. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनन्त स्वरूप निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Department of Commerce

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2023

Case No. AD(SSR)- 08/2023

Subject: Initiation of sunset review investigation concerning imports of anti-dumping duties concerning imports of “Digital Offset Printing Plates” (DOPP) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Vietnam, and Taiwan.

F. No. 7/20/2023-DGTR.—M/s Technova Imaging Systems (P) Ltd (hereinafter referred to as the ‘applicant’), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), seeking initiation of a sunset review investigation for continued imposition of anti-dumping duties levied on imports of “Digital Offset Printing Plates” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Vietnam and Taiwan (hereinafter referred to as the “subject countries”).

2. In terms of Section 9A (5) of the Act and Rule 23 (1B) of the AD Rules, the anti-dumping duties imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review the need for the continued imposition of the anti-dumping duties, and to

assess whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether there is a need for the continued imposition of the anti-dumping duty, and whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

A. Background

3. The original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide Notification No. 6/7/2019-DGTR dated 16.05.2019. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 6/7/2019-DGTR dated 15.05.2020, recommending the imposition of definitive anti-dumping duties.
4. On the basis of the said recommendation, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Custom Notification No.21/2020-Customs (ADD) dated 29.07.2020 on the imports of the subject goods, originating in or exported from subject countries. The current anti-dumping duties are in force up to 28.07.2025.

B. Product under Consideration

5. The product under consideration in the present investigation is Digital Offset Printing Plates (“product under consideration” or “PUC” or “subject goods” or “Digital Plates” or “Digital Offset Printing Plates”).
6. In the original investigation, the product scope concluded by the Authority was as under:

“The product under consideration is “Digital Offset Printing Plates”. Digital offset printing plates are used in the printing industry for transferring data as an image onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets or poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of the image from a ‘computer to the plate’ (CtP) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image. Digital Plates are made from high purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Offset Printing Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The range includes plates that require chemicals for processing the plates; and also, environmentally friendly that require no chemicals or water for processing. The coating formulations vary for different types of plates. There are three types of digital offset printing plates namely,

- i. Thermal Plates;
- ii. Violet Plates;
- iii. CtCP/UV CtP Plates.

The Authority has taken note of post-disclosure comments and holds that all types of Digital Offset Printing Plates in all dimensions and thicknesses are covered within the scope of the product under consideration. However, waterless CtP plates are excluded from the scope of the PUC for reasons elaborated above.

7. The present investigation being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as in the original investigation.
8. The parties to the present investigation may provide their comments on the PUC and propose PCNs, if any, within 15 days of circulation of the non-confidential version of the application filed before the Authority as indicated in paragraph 29 of this initiation notification.

C. Like Article

9. The applicant has submitted that the subject goods produced by them and the subject goods imported from the subject countries are like articles. There is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and those produced by the Petitioner. Digital Plates produced by the Petitioner and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Petitioner are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Domestic Industry & Standing

10. The application for the sunset review investigation has been filed by M/s Technova Imaging System (P) Ltd. The applicant is not related to the exporters or importers of the alleged dumped article. However, the applicant has imported insignificant volumes of the subject goods from both subject and non-subject countries owing to the reason of maintenance regular shutdowns of two of its manufacturing units. The applicant has certified that the imports made by them during the POI were in small quantities as compared to their production of the subject goods. Apart from the applicant, there is one other major producer in India, viz. HL Printech Solutions Pvt Ltd. Out of the total domestic production in India, the applicant's production share amounts to 96%. Since the production of the applicant accounts for a major proportion of the total production of the subject goods in India, the applicant satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

E. Subject Countries

11. The subject countries for the present investigation are China PR, Japan, Korea RP, Vietnam, and Taiwan.

F. Period of Investigation

12. The period of investigation (POI) for the present sunset review investigation is from April 2022 to March 2023 (12 months). The injury examination period is from 1st April 2019 - 31st March 2020, 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, and the POI.

G. Procedure

13. The sunset review investigation will cover all aspects of the final findings published vide Notification No. 6/7/2019-DGTR dated 15.05.2020, recommending the imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.
14. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 of the Rules shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

H. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping**Normal Value for China PR**

15. The consistent practice of the Authority has been to treat China PR as a non-market economy, unless the producers from China PR demonstrate that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sales of the subject goods in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995.
16. Therefore, for the purpose of initiation of the present investigation, the normal value has been constructed based on the estimates of the cost of production of the applicant's duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.

Normal Value for Japan, Korea, Vietnam, and Taiwan

17. The applicant proposed to compute the normal value for the subject countries based on the cost of production of the applicant, duly adjusted for the materials, utilities, and labor to reflect the costs in the subject countries.
18. The Authority, for the purpose of initiation, has *prima facie* determined the normal values for Japan, Korea, Vietnam and Taiwan on the basis of cost of production of the applicant duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

Export Price

19. The Authority has considered the CIF price of the subject goods for the determination of Net Export Price (NEP). The Authority has thereafter made necessary adjustments to these prices to arrive at the ex-factory price.

Dumping Margin

20. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin is above the *de minimis* level and is significant with respect to the product under consideration from the subject countries. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject countries.

I. Likelihood vis-a-vis Injury and Causal Link

21. The quantity of imports of the subject goods from the subject countries has remained high despite the existence of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries. In view of the same, the Authority has examined the *prima facie* likelihood of dumping or recurrence of injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duty. The Authority has also *prima facie* examined the continuation of existing duties based on the grounds alleged in the application.
22. Furthermore, the applicant has claimed the likelihood of injury based on factors such as the positive dumping and injury margins, the history of dumping, capacities available in the subject countries and capacity expansion, the lack of domestic demand in the subject countries, and the likely impact of recurrence of dumping on the domestic industry in the event of cessation of duties. There is *prima facie* evidence regarding the likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty.

J. Initiation of Sunset Review Investigation

23. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry, and in accordance with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority hereby initiates the present investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

K. Submission of Information

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
25. The known producers/exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
28. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

L. Time Limit

29. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email address dd11-dgtr@gov.in and ddl6-dgtr@gov.in with a copy to adg14-dgtr@gov.in and adv13-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
30. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
31. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

M. Submission of Information on Confidential Basis

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
33. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
34. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
36. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
37. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the application as indicated in paragraph 29 of this initiation notification.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or authorizes its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.
41. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions and other information to all other interested parties.

N. Non-Cooperation

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

Anant Swarup Designated Authority